THE ORISSA APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1973—*contd.*

SHRI C. P. MAJHI (Orissa): Sir, everybody knows that the State of Orissa is economically backward and the reason for its backwardness of the State is well known to everybody. It it the political instability and the natural calamities that affect the State very often which are the causes for its economic backwardness. And, Sir, the political instability has been on account of the fact that the politicians who had headed the Government of the State for the last 25 years have been manipulating the politics of the State.

As a matter of fact, Dr. Mahtab, Mr. Biju Patnaik and Mr. R. N. Singh Deo were there for the last 25 years in the State's administration. And now, my friends of the opposition say that the Government of India has been neglecting the State and that on account of the stepmotherly treatment the State has been backward. But I do not agree with my friends on that. If the leadership of the Stale by Mr. Patnaik, Dr. Mahtab and Mr. R. N. Singh Deo was actually strong, the State would by now have improved a lot...

SHRI SUNDAR MANI PATEL (Orissa): That means you are repeating the same statement that was made by the great Prime Minister...

SHRI C. P. MAJHI: May be. But you cannot deny the realities. Those persons who have now formed a perverted party, were there in the State; they were there in the affairs of the State. And because of their leadership, the State has been neglected.

There are certain districts in the State which are very much developed, and there are certain districts, specially tribal districts—there are 7 tribal districts out of 13—which are extremely backward. And you will be surprised to know, Sir, that the people in these areas are distressed during the lean season of ihe year, especially from the months of July to 25 RSS/73—7 October; most of them depend upon Gov ernment charity and they do not have an) work at present, because the working season is over. The .Government is also not able to take up major works in those areas. They are not only economically backward; they are also educationally backward. They are not able to voice their grievances. They actually lack expression because they belong to Adivasis. because they belong to the weaker sections of the community, they are not able to say what they actually want to say to the Government. So these areas have been very much neglected still today.

My friend, Mr. Singh Deo, was telling that Government has lost a revenue of about one, crore of rupees on account of sal seeds. In this connection I also Want to remind Mr. Singh Deo, that there was a Ferro Vanadium factory, which the Swa-tantra Ganatantra Ministry sold to help their private businessmen. That was sold to private business entrepreneurs at a cost of Rs. 2 lakhs...

SHRI K. P. SINGH DEO (Orissa): Did that ferro vanadium factory produce sal seeds.. .

(Interruptions)

SHRI C. P. MAIHI: That factory had been sold away at a cost of Rs. 2 lakhs; it could have fetched about Rs. 10 lakhs. So these are the things. Some inquiry Is being conducted against some Ministers who were heading the State during the lasi few years. Now some of my hon. freinds of the Swatantra Party have become very much allergic that the inquiries are not being done properly and all that.

Sir, 1 want to say something about the condition of the poor adivasi people in the tribal district. About 75 per cent of the State population is below the poverty line. But in the tribal areas more that 90 per cent people have nothing to fall back upon. In my area, i.e. in the district of Mayurbhanj, the condition of the people has become so distressing that they have left their native villages in search of employment outside the State. Sir, to

[Shri C. P. Majhi]

emove the distress of these adivasis people, some sort of permanent nature of tfork should be undertaken in those areas.

Then 1 would mention about irriga-ion. Irrigation in the tribal districts has jeen very much neglected. In the coastal districts, irrigation facilities are about 50 per xnt of the cultivable land whereas in the ribal areas, tli£ agriculturists do not get iven 5 per cent irrigation facilities. How :an we expect to develop all these weaker sections of the community? Unless some sort of permanent step is taken for the employment, nothing can be done. There is arable land in the area. But the actual amount of irrigation work done is very small and the allotment is extremely poor in comparison to the necessity of that area.

In the matter of communication also, the tribal districts have been neglected. Even many sub-divisional headquarters have not been connected by all-weather roads. I need not mention about the block headquarters. There are block headquarters which do not have communication at all. Unless we improve the communication facilities in those areas, it is impossible to think of the development of the tribal people however much we may talk about it. Unless the basic approach is changed, we cannot expect development.

Another point is regarding the sale of liquor. In the entire State, the liquor is being sold every where. But in the tribal areas, the condition is very bad. You may not get a glass of water in a village. but you will surely get gallons of liquor in every village. It is actually robbing the poor adivasi people of whatever little they earn and they are being exploited by these liquor vendors. Unless prohibition is effected in those areas, the condition of the poor adivasi people will not improve. Sir, with these words I support the Bill. I hope that the condition will improve.

Thank you.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, श्री माझी के शब्दों में उड़ीसा की 75 प्रतिशत आबादी बिलो-पावर्टी लाइन है और जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की तो 90 प्रतिशत आबादी बिलो-पावर्टी लाइन है। यह उनका तर्क है और मुझे लगता है कि जो उन्होंने आरोप लगाया आज के वहां के कुछ नेताओं के ऊपर चाहे बीजू पटनायक हों चाहे डाक्टर मेहताब हों तो इतने वर्षों तक कांग्रेस में रहने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार उड़ीसा के इस पिछड़ेपन को मिटाने के लिये तैयार नहीं है और उड़ीसा की ओर किसी प्रकार का ध्यान देने को तैयार नहीं है तो आखिर को कांग्रेस को लात मार कर के उड़ीसा की प्रगति के लिये उन्हें प्रगति दल का निर्माण करना पड़ा था । तो यह श्री माझी ने स्वयं में स्वीकार किया है और आप जानते हो कि उड़ीसा अपने देश में ऐसा प्रांत है जो गरीब होने के बावजूद भी देश में सबसे ज्यादा डेमो-क्रेटिक प्रांत है, जिसने कई बार समय-समय पर निर्णय लिया है, समय की आवश्यकता के अनुसार कांग्रेस को भी चुना है और समय की आवश्यकता के अनुसार कांग्रेस को हराया भी है। अन्य बहुत से प्रांत हैं, जहां कांग्रेस का राज्य निरन्तर चलता रहा है, लेकिन उड़ीसा ऐसा प्रांत है जिसने डेमो-क्रेटिक दृष्टि से निर्णय लिया है। इसलिये राज-नैतिक दृष्टि से सूझ-बूझ के लिये उड़ीसा के लोगों की मैं दाद देना चाहता हूं, हालांकि आर्थिक दृष्टि से वह गरीब है, पिछड़े हैं, और उसका कोई कारण है तो यह कि केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के विकास की दृष्टि से योजना नहीं कर पाई, वह समयक योजनाओं का निर्माण नहीं कर पाई और न आज तक उसने किया है। आज, जबकि उड़ीसा का शासन केन्द्रीय सरकार के हाथ में आया है तो एप्रोप्रिएशन के अन्दर जो सबसे पहली डिमांड ले कर वह आई है वह इनेक्शन के सम्बन्ध में है। मैं चाहूंगा कि जब एप्रोप्रिएशन के अन्दर यह डिमांड लेकर वह आई है तो आप हाउस में यह वचन दें कि उसका उपयोग आप करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार की देश की राजनैतिक स्थिति है, जिस प्रकार का आर्थिक क्राइसिस देश के अन्दर है उससे

लगता नहीं कि कांग्रेस की आज यह हिम्मत हो कि वह कहीं पर चुनाव कराये। आज सारे देश में लोक सभा और विधान सभाओं के उपचुनाव पेंडिंग हैं, लेकिन कहीं भी कांग्रेस चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। जहां भी चुनाव कराया और जो परिणाम कांग्रेस दल के लिये आया है उसको देखते हुये कांग्रेस आज चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी ऐसा लगता है, छः महीने टालने की बात चल रही है। जब कि उत्तर प्रदेश में टालने की बात है तो फिर उड़ीसा जैसे प्रांत में जहां कि कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है और भी इसकी आशंका है। जिस प्रकार से अलग अलग प्रांतों में जहां जहां सूबेदारों की नियुक्ति हुई थी, वहां वहां वे सूबेदार जिस प्रकार से असफल रहे हैं वह आपको ज्ञात है। उड़ीसा में जिनकी नियुक्ति हुई उनको तो विधान सभा से भी जाना पड़ा और हमारे इस सदन से भी हाथ धोना पड़ा, न इधर की रहीं और न उधर की रहीं, जिस प्रकार की गति श्रीमती नन्दनी सत्पथी की हुई है उसको देखते हुये ऐसा लगता नहीं कि उड़ीसा के अन्दर चुनाव करायें। उड़ीसा के अन्दर तो आज हालत यह है जिस निर्वाचन क्षेत्र, कटक, से वह चुन कर आई थीं और जहां सारे हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों ने पैसा उनके सहयोग के लिये लगाया, उस कटक की म्युनिसपैलिटी भी उनके हाथ से चली गई। कुछ दिनों पहले यह दावा किया गया कि विधान सभा के लिये कटक में हमारा बहुमत है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो उसके बाद हालत यह है कि वहां पर म्युनिसपैलिटी भी उनके हाथ में नहीं रही, उसमें भी नहीं जीत सके। तो मुझे लगता है कि उड़ीसा में आपकी हालत बहुत खस्ता है।

दूसरी डिमांड आपकी एजुकेशन की है। (*Time bell rings*) श्रीमन्, मैं चार पांच मिनट में खत्म कर देता हूं। थोड़ी देर में खत्म करता हूं। जो उड़ीसा में जेइपुर का इलाका है जहां से श्री माझी आते हैं उसमें जो मेडिकल कालेज है वहां उस इलाके के लोगों को ही जगह नहीं मिलती है। वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उनकी मांग है कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को इस कालेज के अन्दर स्थान मिलना चाहिये, लेकिन पूरा रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मिलता है। कौन से कारण हैं इन कारणों के बारे में माननीय मंत्री महोदया स्वयं जांच करेंगी, लेकिन इन पिछड़े हुए लोगों को अपने क्षेत्र में ही स्थान नहीं मिलता है। दूसरी उनकी मांग यह थी और बार एसोसियेशन ने और सब ने मिल कर के यह मांग की कि हमारे यहां पर ला कालेज खोला जाय लेकिन ला कालेज खोलने के बजाय और कुछ खोल दिया। जैसा कि मैंने कहा आज तो वहां पर जो कांग्रेस के, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के नेता कह देंगे वही बात मानी जायगी। डी०सी०सी० के नेता जो कह दें वह तो कर देंगे लेकिन चाहे वहां का सारा समाज, चाहे बार एसोसियेशन और बाकी के सभी लोग और जो मेम्बर आफ कामर्स वगैरह हैं वह सब यह मांग करें कि हमारे क्षेत्र में ला कालेज होना चाहिये लेकिन ला कालेज होने के बजाय जैसा कि कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि बी-एड० होना चाहिये तो बी-एड० कालेज खोलने के लिये सरकार तैयार है। तो वास्तव में उस क्षेत्र की क्या आवश्यकता है, उस क्षेत्र के जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे या पहले थे, उनकी क्या मांग थी, इस बारे में सरकार को जानकारी करके कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आज तो निर्णय लेने का अगर दायित्व है तो केन्द्रीय सरकार के ऊपर आता है।

लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि कोरापुट की जो घटनाएं हैं और वहां पर जैसा कुछ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वहां के एस०एच०ओ० ने और सब इंस्पेक्टर आफ पुलिस ने वहां के व्यापारियों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया और उसके बाद जो कोर्ट है उसने डिसीज़न दे दिया कि :—

The Sub-Divisional Officer has two Sub-Inspectors, Shri Araku and Shri Bariq and one Havildar, Shri Jaggu Prasad, who have committed offences under sections 211 and 223 I.P.C.

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

तो जो इस प्रकार की बात कोरापुट में हो गई, उसके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदया से चाहूंगा कि जहां अगर कोर्ट ने होल्ड कर दिया तो वह पोलिटिकल प्रोटेक्शन के आधार के ऊपर इस प्रकार के आफिसर्स का बचाव नहीं करें, और केन्द्रीय सरकार अब तो कम से कम निष्पक्षता से उड़ीसा में शासन चलाएगी और इस प्रकार के लोग जो जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके विरुद्ध कांग्रेस के नेताओं के कहने के कारण से तो आप ऐक्शन लेंगे--इस प्रकार का आश्वासन क्या आप इस सदन को देंगी?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI S. S. MARISWAMY): The House stands adjourned till eleven A.M. tomorrow.

The House then adjourned at one minute past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 4th September 1973.

MGIPRRND-25 RSS 73-Sec II (N)-5-l 1-73—595 Copies.